GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] No. 225] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद 13, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 193

DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941 [N.C.T.D. No. 193

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. 01/2019-राज्य कर

फा. सं. 03(43)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/406.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में सं. फा. 03(42)/ वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/746, तारीख 23 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्यांक 48/2017-राज्य कर, तारीख 23 नवम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र, दिल्ली माल और सेवा कर के अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो, ;

परंतु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा । " ;

- (ii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने "पूर्व आयात आधार पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- 2. यह अधिसूचना 15 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 48/2017 - राज्य कर, तारीख 23 नवम्बर, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में सं. फा. 03(43)/ वित्त (राज.-1)/2019-20/ डीएस-VI /746, तारीख 23 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2019

No. 01/2019-State Tax

F. No. 3 (43)/Fin. (Rev-I)/2019-20/DS-VI/406.—In exercise of the powers conferred by section 147 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) No. 48/2017-State Tax dated the 23rd November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV *vide* number No. F. 3 (42)/Fin. (Rev-I)/2017-18/DS-VI/746 dated the 23rd November, 2017, namely:—

In the said notification,

(i) In the Table, the column number (2) against S. No.1, after the entry, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided that goods so supplied, when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports, shall be used in manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempted goods) and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the jurisdictional commissioner of GST or any other officer authorised by him within 6 months of such supply,;

Provided further that no such certificate shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods.";

- (ii) In the Explanation against serial number 1 the words "on pre-import basis" shall be omitted.
- 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of January, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: The principal notification No. 48/2017- State Tax dated 23rd November, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3 (42)/Fin. (Rev-I)/2017-18/DS-VI/746 dated the 23rd November, 2017.